



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]
No. 277]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2000/अग्रहायण 10, 1922
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2000/AGRAHAYANA 10, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2000

सं. 44 (आर ई-2000)/1997—2002

विषय : (i) विदेशी सहायता में से आयात के संबंध में सीधे भुगतान/वायदा प्रक्रिया के पत्र के तहत भारतीय आयातकों से रुपया जमा।

(ii) भारत सरकार को विदेशी ऋणों के मद्दे सीधे भुगतान/वायदा प्रक्रिया के पत्र के तहत किए गए आयात के संबंध में आयातकों द्वारा देय ब्याज।

फा. सं. 01/89/214/0008/एएम 01.—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार उपर्युक्त विषय पर प्रक्रियाओं में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

तदनुसार, सार्वजनिक सूचना संख्या 174 (पीएन)/92-97 दिनांक 9 नवम्बर, 1993 और संख्या 31-आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 10 अगस्त, 1983 के अतिक्रमण में आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों को भुगतान हेतु विदेशी सहायता के तहत सीधे भुगतान/वायदा प्रक्रिया के पत्र देने वाले आयातकों से रुपया देनदारी और ब्याज प्रभारों को निम्नानुसार संचालित किया जाएगा:-

(क) समतुल्य रूप्यों के बारे में सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयातकों को सूचित किया जाएगा। दानकर्ता द्वारा यथा लागू मूल्य तारीख जिसपर भुगतान किया गया हो आपूर्तिकर्ता/सलाहकार को अदा की गई मुद्रा के संबंध में सरकारी सौदों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बिक्री दर आयातक से रुपया देनदारियों को निर्धारित करने का आधार

बनेगी। आपूर्तिकर्ता/सलाहकार को भारतीय रूपयों में सीधे भुगतान करने के मामले में वसूली उसी राशि के बराबर होगी। तथापि, जहां आपूर्तिकर्ता/सलाहकार को अदा की गई मुद्रा वह मुद्रा हो जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक दर अधिसूचित न करता हो तब दानकर्ता द्वारा दिए गए ऋण/सहायता की मुद्रा को सरकारी सौदों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक दर लागू करने के लिए आधार के तौर पर अपनाई जाएगी।

(ख) (i) आयातक जो केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उपर (क) अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा भारी मात्रा में वित्तपोषित स्वायत्त निकायों पर रूपया देनदारी हेतु देय ब्याज निम्नानुसार होगा:-

(क) वे मामलें जहाँ प्रदायक/परामर्शदाता को भुगतान की तारीख से 90 दिनों के भीतर रूपए जमा कर दिए जाएँ।	भुगतान की तारीख से रूपए जमा करने की तारीख के 90 दिनांक तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोनों दिन सम्मिलित होंगे
(क) वे मामलें जहाँ प्रदायक/परामर्शदाता को भुगतान की तारीख से 90 दिनों के बाद जमा किए जाएँ।	रूपए डिपोजिट की तारीख से पहले 90 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष और 90 दिनों से अधिक पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोनों दिन सम्मिलित होंगे

(ii) अन्य निर्यातकों के लिए, जब तक कि दूसरी तरह से विशेष रूप से अनुमोदित हो, देय ब्याज निम्नलिखित अनुसार होगा:

(क) वे मामलें जहाँ प्रदायक/परामर्शदाता को भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर रूपए जमा कर दिए जाएँ।	भुगतान की तारीख से रूपए जमा करने की तारीख के 30 दिनों तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोनों दिन सम्मिलित होंगे
(क) वे मामलें जहाँ प्रदायक/परामर्शदाता को भुगतान की तारीख से 30 दिनों के बाद जमा किए जाएँ।	रूपए डिपोजिट की तारीख से पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष और 30 दिनों से अधिक पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोनों दिन सम्मिलित होंगे

3. ब्याज का भुगतान जैसाकि ऊपर "ख" पर है, उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे आयात किया जाए।
4. आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रूपये से कम की राशि को पूरा रूपया करके चालान के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली के साथ दिया मंत्रालय के सीएए एण्ड ए, डीईए लेखा में जमा करें और प्राप्त चालान की एक प्रति आर्थिक सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, "बी" विंग 5वाँ तल, जनपथ भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए।
5. सभी निर्यातक रूपए देयता में उपरोक्त परिवर्तन नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त ढंग से सरकार के खाते में अपने बैंकों के माध्यम से आवश्यक रूपए जमा किए जाएँ।
6. ये आदेश 1 दिसम्बर, 2000 से प्रभावी होंगे और 1-12-2000 को या उसके पश्चात भारत सरकार को विदेशी ऋण/क्रेडिट/अनुदान से प्रदायक/परामर्शदाता के किए भुगतान से संबंधित लेन-देन तदनुसार नियमित किए जाएंगे।
इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 1st December, 2000

No. 44 (RE-2000)/1997—2002

Subject : (i) Rupee deposits from Indian Importers under Direct payment/Letter of Commitment Procedure in respect of imports financed out of External Assistance.

(ii) Interest payable by Importers in respect of imports made under the Direct payment/Letter of Commitment Procedure against foreign Loans/Credits/Grants to Government of India.

F. No. 01/89/214/0008/AM 01.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997–2002, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments to the procedures on the above subject:

Accordingly, in supersession of Public Notices No. 174(PN)/92-97 dated 9th November, 1993 and No. 31-ITC(PN)/83 dated 10 August, 1983, the Rupee liability and the interest charges due from the Importers resorting to Direct Payment/ Letter of Commitment procedure under external assistance for payment to the suppliers/ consultants will be regulated as under:

(A) The Rupee equivalent will be intimated to the importer by the Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. Selling rate notified by RBI for Government transactions relevant to the currency paid to the Supplier/ Consultant as applicable for value date on which payment was made by the Donor will form the basis for determining Rupees dues from the Importer. In case of direct payment to the Supplier/ Consultant in Indian Rupees, the recovery will be equal to the same amount. However, where currency paid to the Supplier/ Consultant is a currency for which RBI does not notify the rate, then the currency charged to the Loan/ Grant account of the donor will be adopted as the basis for applying the RBI Selling rate for Government transactions.

(B) (i) The interest payable for the Rupee liability on (A) above by the Importers who are Central/ State Public Sector Undertakings or autonomous bodies substantially financed by Central/ State Government(s) will be as indicated below:-

(a) Cases where Rupee deposits are made within 90 days from the date of payment to the Supplier/ Consultant	@ 12% per annum upto 90 days from the date of payment to the date of Rupee deposit, both days inclusive
(b) Cases where deposits are made after 90 days from the date of payment to the Supplier/ Consultant	@ 12% per annum for the first 90 days and @ 15% per annum in excess of 90 days from the date of Rupee deposit, both days inclusive

(ii) For other Importers, the interest payable would be as indicated below, unless specifically approved otherwise:

(a) Cases where Rupee deposits are made within 30 days from the date of payment to the Supplier/ Consultant	@ 12% per annum upto 30 days from the date of payment to the date of Rupee deposit, both inclusive
(b) Cases where Rupee deposits are made after 30 days from the date of payment to the Supplier/ Consultant	@ 12% per annum for the first 30 days and @ 18% per annum in excess of 30 days from the date of payment to the date of Rupee deposit, both days inclusive

3. Payment of interest as at (B) above will not be applicable in cases where imports are made directly by Ministries/Departments of Government of India and the State Governments.

4. The Rupee amount rounded off to the nearest one rupee as intimated by Aid Accounts & Audit Division, Department of Economics Affairs should be deposited with interest as applicable, to the account of CAA&A, DEA, Ministry of Finance with the RBI, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi through Challan and a copy of receipted challan should be sent to the Aid Accounts and Audit Division, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, 'B' Wing, Vth Floor, Janpath Bhavan, New Delhi-110 001.

5. All the importers should note the above change in the rupee liability and ensure that necessary Rupee deposits are made by them through their banks to the Government Account in the above manner.

6. These orders take effect from 1st December, 2000 and the transactions relating to payments made to the Suppliers/ Consultants from out of the External Loan/ Credit/ Grant to the Government of India on or after 1-12-2000 will be regulated accordingly.

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade